

**बिहार सरकार**  
**पर्यावरण एवं वन विभाग**

प्रेषक,

रत्नेश झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक--...../03/2016

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) योजना अन्तर्गत कुल ₹ 835.87 लाख (आठ करोड़ पैंतीस लाख सतासी हजार ₹ मात्र) के योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य के विभिन्न जिलों में परंपरागत सुरक्षित वनों को पुनर्वासित करने एवं सन्निकट अवस्थित लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने/रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) 60:40 योजना अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.- MoEF & CC (NAEB) : 6-1/2015-B-III दिनांक-31.07.2015 एवं पत्रांक-F.No.- MoEF & CC (NAEB) : 6-1/2015-B-III दिनांक-30.10.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत योजना एवं राशि विमुक्ति के आलोक में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 835.87 लाख (आठ करोड़ पैंतीस लाख सतासी हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में वर्तमान में मंत्रालय द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹ 208.97 लाख (दो करोड़ आठ लाख सतान्चे हजार ₹ मात्र) मात्र की विमुक्ति आदेशानुसार एवं इसके अनुपातिक राज्यांश राशि मात्र ही तत्काल व्यय किया जायेगा तथा शेष राशि का व्यय पुनः मंत्रालय द्वारा विमुक्ति आदेश के आलोक में की जायेगी। साथ ही संबंध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि को कोषागार से एक मुश्त निकासी कर राज्य वन विकास अभिकरण, बिहार के PL खाता-PLA 262 में जमा किया जायेगा तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से उक्त स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन पर इस राशि का व्यय किया जायेगा।

2. भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से 50:50 योजना के तहत दी गयी स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति आदेश के आलोक में यह स्वीकृति दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट नयी फण्डिंग पैटर्न के अनुसार उक्त योजना को सम्प्रति 60:40 के तहत क्रियान्वित किया जाना है। तदालोक में उक्त योजना की स्वीकृति 60:40 के तहत दी गयी है।

L

3. इस राशि की निकासी निम्नवत् मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत की जायेगी:-

केन्द्रांश :- पूरी योजना राशि का 60 प्रतिशत (Flexi Fund सहित) कुल ₹ 501.52 लाख (पाँच करोड़ एक लाख बावन हजार ₹ मात्र) की निकासी मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, उप शीर्ष-0201-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत मिशन), माँग संख्या-19, विपत्र कोड-P2406041010201 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी के तहत मूल उपबंधित राशि एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-601 दिनांक-19.02.2016 द्वारा बिहार राज्य आकस्मिकता नीधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त उपबंधित राशि के अन्तर्गत।

राज्यांश :- पूरी योजना राशि का 40 प्रतिशत (Flexi Fund सहित) कुल ₹ 334.35 लाख (तीन करोड़ चौतीस लाख पैतीस हजार ₹ मात्र) की निकासी मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, उप शीर्ष-0301-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत मिशन), माँग संख्या-19, विपत्र कोड-P2406041010301 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी के तहत मूल उपबंधित राशि एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-601 दिनांक-19.02.2016 द्वारा बिहार राज्य आकस्मिकता नीधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त उपबंधित राशि के अन्तर्गत।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से की जायेगी एवं निकासी की गयी राशि को एक मुश्त राज्य वन विकास अभिकरण, बिहार के PL खाता-PLA 262 में जमा कर दी जायेगी।

5. प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-24.02.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक-707 दिनांक-26.02.2016 द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा एवं संचिका के पृष्ठ-20/टि० पर माननीय विभागीय मंत्री का प्रस्ताव में स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रारूप में पृष्ठ-21/टि० पर दिनांक-04.03.2016 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। बजट उपबंध एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्ति आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

✓

9. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र संघारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना का होगा। आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

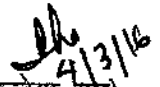
ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-योजना बजट- 12/2014 847 /प०व० पटना-15, दिनांक -04/03/2016

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
4/3/16  
(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

Authentication No. MEF (NAEB): 12/2015-16

F. No. MoEF&CC (NAEB): 6-1/2015-B-III  
Government of India  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
National Afforestation & Eco-Development Board  
7<sup>th</sup> Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex  
Lodhi Road, New Delhi - 110 570

Dated: 30.10.2015

To  
The Pay & Accounts Officer,  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Indira Paryavaran Bhawan  
Jor Bagh Road,  
New Delhi - 110005

**Subject: Sanction of Project under the National Afforestation Programme (NAP) Scheme for implementation by State Forest Development Agency (SFDA) Bihar Approval of Revised work-programme and payment sanction during 2015-16 – Balance amount of 1<sup>st</sup> installment for General Category- regarding.**

Sir,

In continuation of this office Sanction Order No. MoEF&CC (NAEB): 6-1/2015-B-III, dated 31-07-2015, I am directed to convey the sanction of the President of India to the release of Rs.97.68 lakh (Rupees Ninety seven lakhs and sixty eight thousand only) as balance of first installment towards Grants-in-Aid to SFDA Bihar project under the National Afforestation Programme Scheme for the financial year 2015-16-Revised- (Plan) Non-Recurring (General Category). ~~Out of the Revised Total outlay of the project 50% share would be provided by the Central Government & matching share would be provided by the State Government. The revised funding pattern of the Scheme from 2015-16 onwards.~~ The project shall be implemented by the SFDA Bihar for carrying out 2500 hectares of Advance Work, 1756 hectares of creation and maintenance of plantation for 1<sup>st</sup> year, 2<sup>nd</sup> year and 3<sup>rd</sup> year in 3885 hectares, 1950 hectares and 5085 hectares respectively at a total cost of Rs. 752.29 lakh (Rupees seven crore and fifty two lakhs twenty nine thousand only) @ wage rate of Rs. 194.00 for the year 2015-16. The 50% Central Share including 10% Flexi Fund (revised) is Rs.417.94 lakhs. The FDA-wise approved work programme of SFDA, Bihar is given in Annexure. The unspent balance of Rs. 0.146 lakh has been taken into account in the earlier release.

2. The Scheme will be implemented on the revised funding pattern which is anticipated to be Centre: State:: 50:50 (as against 100:0 earlier). The first installment release is subject to the condition that a matching share should come from the State Govt. (retrospectively) once the changed funding pattern is notified.

3. The advance work being sanctioned hereby for 2015-16 is provisional and may change subject to reviewing at the time of 2<sup>nd</sup> installment release during 2015-16 on receipt of all relevant documents/certificates by the implementing agency.

4. All relevant documents/ certificates would be submitted by the implementing agency after completion of Annual Work Programme of 2015-16. The pattern of assistance of rules governing as per the Revised Operational Guidelines has received as per the approval of the Ministry of Finance.

5. The grants-in-aid will be regulated in accordance with the provisions contained in the Guidelines of Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, New Delhi. The Grants-in-Aid is also subject to the Chapter 9 of the General Financial Rules, 2005, as amended

from time to time, read with the Government of India's decisions incorporated there-under, and any other guidelines which may be issued in this regard, and in particular to the following conditions:-

- (i) All relevant information and documents/ certificates as required under NAP Guidelines have been received.
- (ii) The pattern of assistance of rules governing such grants-in aid have received the approval of the Ministry of Finance, as required under Govt. of the Decision No (1) under DFPR - Rules 20.
- (iii) No staff is to be provided specifically for the scheme.
- (iv) Assets acquired wholly or substantially out of Government Grants shall not be disposed off without obtaining the prior approval of the sanctioning authority of Grants-in Aid.
- (v) The Accounts of Bihar SFDA shall be audited by C&AG or by any person authorized by him on his behalf in accordance with the provisions laid down in section 14 of the C&AG (DPC) 1971 as amended from time to time.
- (vi) The Accounts of Bihar SFDA shall be open for inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of C&AG (DPC) Act 1971 and Internal Audit Party by the Principal Accounts Office of the Ministry or Department whenever it is called upon to do so.
- (vii) The Bihar SFDA shall furnish Utilization Certificate including the State's Share along with its request for release of Grants-in Aid certifying that the fund released to them for which Utilization Certificate has been issued has been utilized exclusively in pursuance of objectives envisaged in the Rules/ Memorandum of Bihar SFDA and that the Grant shall be spent with the extant instruction/ rules and with the approval of competent authority in each case.
- (viii) Performance cum achievement report of Bihar SFDA shall be furnished within prescribed time limit.
- (ix) Noted at Sl.No.12 in the Register of Grants (General).
- (x) Bihar SFDA will spend Grants-in Aid exclusively in pursuance of the objectives envisaged in Rules/Memorandum of Bihar SFDA, for the purpose it is being sanctioned.
- (xi) Grants-in Aid to Bihar SFDA is subject to the Economy Instruction issued from time to time by the Ministry of Finance or by any Competent Authority so designated.
- (xii) Grants-in Aid shall be utilized before the end of the current financial year 2015-16 and unspent balance, if any, will be refunded by Bihar SFDA to the Government of India.
- (xiii) Bihar SFDA will maintain and will present their annual accounts in the standard format as required under GFR 209(xiii).
- (xiv) In case of Non-recurring Grant for specified object :-
  - a. Bihar SFDA will have to spend the amount sanctioned to them up to 31.03.2016.
  - b. Utilization Certificate of Grants-in Aid sanctioned during the year 2015-16 from Bihar SFDA would have to be submitted as required under GFR 202(1) read with the Form GFR 19-A.

6. SFDA will take necessary steps to ensure the minimum survival of plants after planting under the NAP Scheme from the end of 1<sup>st</sup> to fifth year as fixed for various PDAs vide our O.M.No.8-1/2005-B-1 dated 26.11.2009 and 16.12.2009. The survival percentage of plantation should be reflected in the last Quarterly Progress Report submitted ending 31<sup>st</sup> March to this Ministry.

7. The expenditure involved will be met from within the Sanctioned Budget Grant under No. 31 Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Major Head 3601.02.665.04.01.31 Grants-in-Aid for the year 2015-16 (Plan).

8. In accordance with the revised procedure the Reserve Bank of India may please be advised to pass on the credit to the Central Accounts Section, Nagpur for transferring the funds to the accounts of Government of Bihar and in debit the amount to the Account of Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, New Delhi.

9. The State Government of Bihar would make provisions in their budget and on receipt of funds from RBI, release the grants of above funds within 15 days of the issue of this sanction letter to the SFDA, the details of which are given below, under intimation to this office.

Name and FDA	Name of Bank where A/c of SFDA held	Name and complete address of the bank branch	IFSC/MICR Code/ Bank Branch Code	Type of Account	Account No.
SFDA Bihar	State Bank of India	SBI, Patna Secretariat, Bhawan, Patna-15	IFSC-SBIN-0000153 MICR-800002036	Current	31679378333

10. The project will be implemented by the implementing agency in the identified area only strictly as per the Revised Operational Guidelines-2009 of National Afforestation Programme Scheme including the following:-

- The funds received by the SFDA shall be deposited in its exclusive and separate current account in a Nationalized Bank, which would be operated jointly by its Chairperson and the Member Secretary.
- The SFDA shall transfer the full amount earmarked for all FDAs within 7 days of receipt of funds from the NAEP, MoEF&CC based on the approved work programme.
- The funds received by the FDA from SFDA shall be deposited in its exclusive and separate current account in a Nationalized Bank, which would be operated jointly by its Chairperson and the Member Secretary. If the stipulation regarding joint signatures of the CEO and the Chairperson is found to cause undue delay in banking transactions especially in cases where the headquarters of the Chairperson and CEO are quite far apart, the SFDA may devise a mechanism to overcome the problem, ensuring adequate accountability at the same time.
- The FDA shall release the amount for all the JFMCs/EDCs by ECS or demand draft within 15 days of receipt of funds from the SFDA based on the fund requirement, progress of implementation and utilization of earlier releases.
- The respective JFMCs/ EDCs shall deposit the funds thus received from the FDA in their exclusive and separate account in a Nationalized Bank/ a Cooperative Bank or a Post Office, which would be jointly operated by the President and the Member Secretary.
- Each JFMC/ EDC shall submit a quarterly statement of accounts and progress of works carried out by them to the FDA.
- The FDA shall submit a comprehensive annual report on the progress of works and utilization of funds in respect of all JFMCs/ EDCs to the respective State Forest Development Agency. However, these details have to be furnished by the FDA each time they seek for release of the next installment of funds under the project.

- h) The Project shall be implemented in the areas as indicated in the project proposal and approved by the NAEB, MoEF&CC
- i) The interest amount if any, accrued on the deposits of these funds shall be treated as part of the SFDA's additional resources and would be adjusted towards further installments of the grant.
- j) The funds released under the scheme shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or his nominated officer. Any other agency/ officer (s) authorized by NAEB shall have the right of access to the books and accounts of the SFDA/ FDA/JFMCs and EDCs for the funds received under the project
- k) The SFDA shall be responsible for guidance, coordination, supervision, periodical reporting and monitoring the implementation of the project by their constituent FDAs/JFMCs/ EDCs. The project shall be monitored periodically by the respective State Forest Department and the officials of NAEB, MoEF&CC and all assistance for this purpose will be rendered by the SFDA.
- l) The project should be completed within the approved project period. The SFDA shall furnish 2 copies of detailed report to NAEB as per the format prescribed by NAEB within two months of completion of the project.
- m) NAEB reserve the right to terminate the grant at any stage if it is convinced that the grant has not been properly utilized or appropriate progress has not been made.
- n) In case the FDA fails to execute the project within the stipulated time, including such extensions as may be granted by NAEB, NAEB may, in its discretion, require the SFDA to refund the grant in whole or in such part on account of the FDA along with interest thereon as NAEB may specify.
- o) There will be no diversion of funds from one FDA to another FDA or one JFMC/ EDC to another save in exceptional circumstances and with the prior approval of NAEB.
- p) The SFDA will submit non-diversion and non-embezzlement certificate each time a request for release of grant is made to NAEB.
- q) The auditing of accounts of the SFDA/FDAs will have to be carried out through a reputed Chartered Accountant who is also on the panel of C&AG.
- r) The SFDA shall also submit a certificate to the effect that all conditions laid down in the guidelines and the sanction order are being followed each time a request for release of grant is made to NAEB.
- s) FDA/ JFMCs will maintain a record of all assets created under the project as per GFR 151.
- t) Contractors / middlemen/ intermediate agencies are not permitted to be engaged for execution of any of the works under the scheme so that full benefits of wages to be paid reach the workers.
- u) *Evidence of deposit of TDS/Service Tax in case of contract payments and CST in case of purchase of taxable goods.*
- v) *Payment towards wages/ remuneration as well as other contractual obligation should be made through bank accounts of recipients. In case of contractual engagement copy of PF & ESI may be submitted.*
- w) Except for supervening impossibilities, the Chairperson and the Member Secretary of the SFDA/FDA shall be solely responsible and accountable for successful implementation of the project.
- x) The SFDA should confirm that MoU between FDA and JFMC/EDCs as well as between FDA and SFDA as per para 2.2 of operational guidelines.
- y) The SFDA will ensure complete compliance with operational guidelines of NAP and conditions mentioned in the previous sanction orders.

11. The payment sanctioned above is provisional. The final adjustment will be made after receipt of the item wise physical and financial Progress Report, utilization certificate and Audited Expenditure figures from the implementing agency at the time of 2<sup>nd</sup> installment release. The Progress Report of each quarter is to be sent regularly.

12. The implementing agency is requested to ensure that the Central assistance being released will be gamfully utilized in furtherance of the approved work programme without any time over-run under the project scheme. The proposed area coverage under the work programme should not be overlapping with any other Central State scheme and there should be no duplication of central / external assistance in any case.

13. The implementation of the project and maintenance of plantations raised there under that spill over to the next year shall be the responsibility of the State Government unless the NAP scheme is continued.

14. As per Para 9.2, the SFDA has to commission independent evaluation of each FIDA project twice during the project cycle. The evaluation report of the Action Taken Report could be mandatory for release of second installment.

15. The SFDA Bihar needs to implement the programme of creation work in the new area strictly as per the Geo-references (Longitude - Latitude) submitted along with the project proposal for 2015-16. The SFDA will certify that the creation work has been carried out in the area where Geo references have been submitted for advance work during 2014-15. *Satellite photographs with dates and GPS coordinates should be furnished before and after the implementation of each work of the scheme and furnished with the physical progress report. (Say before and after completing Advance Work, Creation and maintenance separately).*

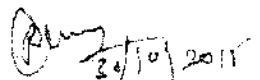
16. The SFDA Bihar was advised to complete the digitization of forest boundary and submit status report which should be complied with.

17. **Out of the total amount released through this Sanction Order, 10% of funds will be utilized as flexi funds as per Guidelines issued by Department of Expenditure (Ministry of Finance) vide OM NO. 55(5)/PF.H/2011 dated 06.01.2014.**

18. The sanction issues under the power delegated to the National Afforestation & Eco-Development Board and with the concurrence of the Finance Division vide their Dy.No. 946/AS(PF) dated 26/10/2015.

Yours faithfully,

Encl.: as above.

  
30/10/2015  
(R.C. Meena)


Assistant Commissioner (Forestry)

Copy to: -

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Bihar, Patna
2. The Secretary, Forest Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Secretary, Finance Department, Government of Bihar, Patna.
4. The Secretary, Planning Department, Government of Bihar, Patna.
5. The Accountant General (A&E), Government of Bihar, Patna.
6. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office MoEF&CC, Bhūbaūeshwar.
7. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests/ Nadal Officer of NAP, Government of Bihar, Patna
8. Ministry of Finance, Department of Expenditure, Plan Finance Division, New Delhi.
9. The Manager, Reserve Bank of India, central account Section, Nagpur.



10. Principal Director (Audit), Scientific Department, AICR Building, New Delhi-2.
11. The Coordinator, Regional Centre of NAFB, Jadavpur University, Kolkata.
12. I.G.E.(NAEB).
13. The US (IFD), NAEB.
14. The D.D.O (Cash), NAEB.
15. ACF, NAEB
16. DPA, NAEB
17. Budget and Accounts Division, Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
18. Sanction Folder/ Guard File.

  
 30/11/15  
 (M. Sivagami Selvi)  
 Technical Officer (Forestry)

Details of 2015-16 (Revised)

1.	Total Approved Project Cost (@ wage rate of Rs. 194/- per day)- Revised	Rs. 752.29 lakh
2.	Central Share (50% of APO)	Rs. 376.15 lakh
3.	10% Flexi Funds on Central Share	Rs. 41.79 lakh
4.	Total Outlay for the year 2015-16 (Central Share -Revised) (2+3)	Rs. 417.94 lakh
5.	50% of Central Share (50% of 4)	Rs. 208.97 lakh
6.	Unspent Balance adjusted (as on 31.03.2015)	Rs. 0.146 lakh
7.	First Installment of Central Share already released (5-6)	Rs. 111.14 lakh
8.	Balance of First Installment released (5-(7+6))	Rs. 97.68 lakh

Revised Approved Work Programme for 2015-16  
 Central Sector Scheme "National Afforestation Programme" (NAP)  
 Agency - State Forest Development Agency Bihar  
 State-Bihar

Sl. No.	Item of work	Approved Wage rate : Rs. 194.00 per manday	
		Rate (in Rs.)	Physical & Financial Target/Outlay for 2015-16
			Phy.(in ha) Fin.(Rs. in Lakh)
1	2	3	4
1	Aided Natural Regeneration	9750	
	Admissible Rate:	25220	
	a) Advance Work	8030	400
	b) Creation	5898	1005
	b) Maintenance I Year	2678	2150
	II Year	2328	950
	III Year	2328	1450
	Subtotal :	21262	5955
2	Artificial Regeneration	17100	
	Admissible Rate:	44332	
	a) Advance Work	10433	950
	b) Creation	18048	415
	b) Maintenance I Year	5504	995
	II Year	2328	450
	III Year	2328	1620
	Subtotal :	38641	4430
3	Mixed Plantation	17100	
	Admissible Rate:	44332	
	a) Advance Work	10433	1050
	b) Creation	18048	306
	b) Maintenance I Year	5504	600
	II Year	2328	450
	III Year	2328	1615
	Subtotal :	38641	4021
4	Bamboo Plantation	9300	
	Admissible Rate:	24958	
	a) Advance Work	6622	100
	b) Creation	9095	60
	b) Maintenance I Year	3686	140
	II Year	2328	100
	III Year	1261	400
	Subtotal :	22992	800
	Total works (A) :		15206
			752.29
			Central Share (50% of (A))
			376.15
			10% Flexi Fund
			41.79
			Grand Total
			417.94

(M. Sivigami Selvi)  
 Technical Officer (Forestry)

उप सचिव  
 पर्यावरण एवं वन विभाग  
 बिहार, पटना

